| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Goa, Daman & Diu | .. | 1 | 94.7 |
| 5 | Pondicherry (except Mahe, Yanam & Karaikal) | .. | 1 | 100.0 |
| 6 | Chandigarh | .. | .. | 100.0 |
| 7 | Dadra & Nagar Haveli | .. | .. | .. |
| 8. | Lakshadweep | .. | .. | .. |
| | | 17 | 183 | |

*NOTE: This refers to Programme Production Centre at Rajkot.

In addition, studio facilities of Space Applications Centre, Indian Space Research Organisation at Ahmedabad are used by Doordarshan Kendra, Ahmedabad for production of local programmes.

**Earnings of Doordarshan from the Advertisements**

1590. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the details of revenue earnings of Doordarshan from advertisements during the period April—October, 1986;

(b) whether Government propose to continue with the policy of finding sponsors for programmes; and

(c) if so, whether Government propose to ensure that the quality of the programmes does not decline as a result of increased commercialisation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) The gross revenue earnings of Doordarshan from advertisements as available for the period April to September, 1986 are Rs. 45,90,37,398|. The provisional figures for October, 1986 are Rs. 7.15 crores.

(b) and (c) Yes, Sir.

**Clearance of Afforestation Project for Hyderabad and Secunderabad**

1591. SHRI GOPALA RAO RAO : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether an afforestation project proposal of the Andhra Pradesh Government for "Greening" the heavily afforested and denuded areas of Hyderabad-Secunderabad, is under consideration of National Wastelands Development Board (NWDB); and

(b) if so, what are the details of the proposal and the reasons for delay in giving permission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) A project proposal formulated by CHETANA, a Voluntary Organisation, on a "Green Belt around Hyderabad" for assistance from the Federal Republic of Germany is under the consideration of the Government of India.

(b) This project aims at afforesting the periphery of the twin cities of Hyderabad/Secunderabad and taking up a meaningful rural development programme for the benefit of nearly 7 lakh people living in 307 villages around the cities. The project has two components : (i) Green belt development around Hyderabad and (ii) IRD Programme. The project period is 10 years and the cost is estimated at Rs. 150.00

million —30 per cent of which (Rs. 45.00 million) will be borne by the Lead Agency Chetana, which will seek the cooperation and involvement of Government Departments in the project. Foreign aid to the tune of 70 per cent (Rs. 105 million) has been provided in the project report. The project has been posed for assistance from the Federal Republic of Germany.

**बिहार में सेटेलाइट बेस स्टेशन आदि**

1592. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में सेटेलाइट बेस स्टेशन स्थापित करने का कोई कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है, मल्टी एक्सेस रुरल रेडियो स्कीम के अन्तर्गत एक भी सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र नहीं खुला है, छोटे-छोटे दूरभाष केन्द्रों पर इन्टर डायलिंग की सुविधा नहीं है, राज्य में एक तिहाई जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० की सुविधा नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भागलपुर में एक स्वचालित दूरभाष केन्द्र बनाने में काफी लम्बा समय लगने की संभावना है, कई शहरों में दूरभाष केन्द्र के लिए भवन तैयार है पर उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, कई शहरों में जमीन उपलब्ध है, किन्तु उस पर अभी तक भवन का निर्माण शुरु नहीं हुआ है; और

(ग) क्या यह सच है कि गिरिडीह, हाजीपुर और सीतामढ़ी के माइक्रोवेव ट्रांसमिशन उपकरण दूसरे क्षेत्र में भेज दिए गए हैं, यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) (1) पटना में एक भू केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है जिसके माध्यम से बम्बई और मद्रास के लिए सम्पर्क सुलभ है। 16 जिला मुख्यालयों को संचारण माध्यम पहले ही सुलभ करा दिए गए हैं तथा 15 जिलों के लिए स्कीम पर कार्य चल रहा है। शेष 7 जिला मुख्यालयों के लिए संचारण माध्यम हेतु योजना तैयार कर ली गई है। चूंकि सभी जिला मुख्यालय इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं इस प्रकार किसी भी भू-केन्द्र की योजना नहीं है।

(2) भू-लाइनों के माध्यम से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तकनीकी व्यवहार्यताओं के आधार पर एम०ए०आर०आर० पर भी विचार किया जा रहा है।

(3) जहां कहीं सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर इंटर डायलिंग सुविधा का औचित्य बनता है ये सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। विभाग ऐसी आवश्यकताओं पर विचार कर रहा है।

(4) बिहार राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में से 14 में एसटीडी सुविधाएं सुलभ हैं। शेष जिलों के लिए 7वीं योजना में एसटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ख) भागलपुर में टेलीफोन एक्सचेंज का संस्थापन किया जा रहा है और इसके 7वीं योजना में चालू हो जाने की संभावना है।

योजना कार्यक्रमों पर आधारित भवन निर्माण के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाती है लेकिन उपस्करों की कमी के कारण कुछ स्थानों पर एक्सचेंज की संस्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(ग) हाजीपुर में उपस्कर उपलब्ध हैं और सीतामढ़ी तथा गिरिडीह के लिए उपस्कर प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।